

दिनांक : 03 दिसम्बर 2019

श्री रंजित राव शिंदे

M/s

लिफ्ट

श्री रंजित राव शिंदे, राजकीय अधिवक्ता सेवा, संख्या दो
श्री किशोराम शिंदे, अधिवक्ता सेवा, संख्या एक
श्री राजेशलाल शिंदे, अधिवक्ता अधीनस्थ

उपस्थित-

----- 0 -----

निम्नलिखित

प्रकरण संख्या 42/2019 मुंबई नगर
कोर्ट फाईल दिनांक 11 दिसम्बर 2019
अधिवक्ता, 1955 विस्डू आदेश संख्याक
अपील अवकाश एत 225 राजस्थान कोर्टफाईल



----- सेवा

1. मुंबई नगर कोर्ट
2. तहसीलदार कोर्ट
3. तहसीलदार कोर्ट, कोर्ट नगर
4. कोर्ट नगर, कोर्ट नगर
5. मुंबई नगर कोर्ट

श

ना

व

----- अधीनस्थ

1. निम्नलिखित मुंबई नगर कोर्ट
2. कोर्ट नगर मुंबई नगर कोर्ट
3. कोर्ट नगर मुंबई नगर कोर्ट
4. कोर्ट नगर मुंबई नगर कोर्ट
5. कोर्ट नगर मुंबई नगर कोर्ट

2019RMAJU225RTA132 Nimbaram n ors Vs Premaram etc

न्यायालय राजस्थान अपील याचिका, कोर्ट न्यायालय अधिकाारी श्री नरवदन शिंदे, आ.रा.व.स.

अधीनस्थ
अधीनस्थ

संख्या 940 में से एक कदीमी रास्ता है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं
कटापी मार्ग तक आवागमन के लिए अधीनस्थ की खातेदारी के खास
कडवासरानगर तहसील लोहाट में स्थित है, जिसमें स्थित टापी से
सहखातेदारान की खातेदारी भी खास संख्या 935 तक सीमा
लिया का समझन करते हुए कथन किया कि रेप. संख्या एक एवं अन्य
जबल में रेप. की ओर से विज्ञान अधिवक्ता ने अधीनस्थ



अधीनस्थ आदेश अपास्त किया जावे।
पाठित कर दिया गया। अतः अधीन अधीनस्थ स्वीकार की जाकर
न्यायालय द्वारा उसका निरस्त किया बिना ही अधीनस्थ आदेश
के संबंध में अधीनस्थ परतुलन किया गया था, अगर अधीनस्थ
का भी अवसर नहीं दिया गया। अधीन-रेप. की ओर से मौका रिपोर्ट
न्यायालय में प्राप्त होने के बाद उसके संबंध में उच्च-पतरान और सुनवाई
न्यायालय द्वारा कोई स्थान नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट अधीनस्थ
मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इस तथ्य पर भी अधीनस्थ
है। स्वयं पटवारी भी मौका रिपोर्ट तैयार करने में मौके पर नहीं गया।
उपस्थित रहने बावत किसी भी पक्षकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया
होका द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गयी है। मौके पर
तैयार की गयी होती है, अगर आलोच्य प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी
श्री-अधिवक्ता निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में
1955 के मामलों में नियमानुसार मौका रिपोर्ट संबंधित तहसीलदार अथवा
दोहरीते हुए कथन किया कि धारा 251ए राजस्थान कायदाकारी अधिनियम,
अधिवक्ता अधीनस्थ ने तथ्यों एवं अधीनस्थों में वर्णित बिंदुओं को
उभयपक्ष के विज्ञान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। विज्ञान
दोकर अधीनस्थ-अधीनस्थ ने आलोच्य अधीनस्थ को है।

दिसम्बर 2019 को उच्च परतुलन स्वीकार कर लिया गया। जिससे खाते

13/11/19
निदेशक, अखिल भारतीय
विद्यार्थी संघ

उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी अखिल भारतीय की उपाध्यक्ष पर
राज्यीय स्तर पर किया गया एवं उपलब्ध अधिष्ठाता का आशीर्वाद
अधीनस्थ न्यायालय की पदावली में उपलब्ध
आदेशिकाओं के अवलोकन से पाया जाता है कि अध्यापक-अधीनस्थ द्वारा
शौक-रिपोर्ट प्राप्त की आपत्त-प्राप्त-पक्ष किया गया, उसके संबंध में
पक्षकारान की सुनवाई कर अधिष्ठाता न्यायालय के पीठासीन अधिकाारी
द्वारा द्वारा दिनांक 10 सितंबर 2019 को शौका देखा जा आदेशिका
दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के अनुसार लिखित किया गया। दिनांक 11
सितंबर 2019 की आदेशिका में दिनांक 10 सितंबर 2019 को शौका देखा



को सार्वजनिक किया गया।
आदेश अन्तर्गत आदेश 01 दिनांक 10 सीपीसी दिनांक 02 सितंबर 2019
ले विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष को पर प्रदत्त किया है। उक्त परिपत्र में
अपने अधिकाारी का उपयोग करते हुए दावा है, जो अधिष्ठाता न्यायालय
द्वारा दिनांक 25/11/19 रात्रिस्थान काशिकासी अधिष्ठाता के तहत प्रदत्त
उक्त खसरा संख्या 939 में से रास्ता नहीं दावा है। उक्त पूर्व में चल रहे
से देले हुए संहिता है। उसका पक्ष सुना गया। रैप्टी. का कथन है कि
निसक एक सडक है। वह रैप्टी. द्वारा दावा रास्ता अपना अधिष्ठाता
18 दिनांक वाक कडवासरानगर खसरा संख्या 935 से दिनांक हुआ है
किया। उसका कथन है कि पार्सी का खसरा संख्या 939 रकबा 13 बीघा
राज्यीय पत्र माजाराज जाट ले प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का निर्देश
प्रकरण में एक पार्सीपत्र अन्तर्गत आदेश 01 दिनांक 10 सीपीसी
रिपोर्ट करने में अधिष्ठाता न्यायालय द्वारा कोई रैप्टी नहीं की गयी है।
अधिष्ठाता, 1955 के तहत पार्सीपत्र पक्ष किया गया, निसे विद्यार्थी संघ,
इस कारण अधिष्ठाता न्यायालय में द्वारा 25/11/19 रात्रिस्थान काशिकासी
होने से उसका उपयोग अध्यापक-अधीनस्थ की इच्छा पर निर्भर रहता था,

जाने का विवरण अंकित करते हुए अग्रणी का उक्त आपत्त पत्र आपत्त पत्र खारिज कर दिया गया। अतः अपील स्तर पर अग्रणी-अपीलापट के अधिवक्ता द्वारा यह लिया गया आक्षेप कदाई नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्त पत्र आपत्त पत्र खारिज किसे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय पर अपीलापत्र का निरस्तकरण किसे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा शौको मंगायना कर लिया गया, ऐसी स्थिति में प्रथम शौको रिपोर्ट में रही तकलीफी खामियों एवं उनके संबंध में उठायी गयी आपत्तियों का निरकरण स्वतः ही हो जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं शौको मंगायना करने के बाद यह स्थितिगत करते हुए कि शौके पर अन्य पार्श्वोप-रेफरे. की दृष्टि तक आवागमन के लिए परस्परित सारने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, अतः उभयपक्षकारण की सुनवाई के बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय 11 दिसम्बर 2019 पारित किया गया है, उससे अलगत होना पूर्णतः संभव है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलापट्टस स्वीकार किसे जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 11 दिसम्बर 2019 यथावत रखा जाता है।

दिनांक 31/12/19

(न्यायदाल बरहद)
राजस्थान अपील प्राधिकारी, जोधपुर

